छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक - 8 (जनवरी- मार्च 2019)

ईमेलः- **chhattisgarh.sccc@gmail.com** वेबसाइटः- **www.cgclimatechange.com**

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

सम्माननीय पाठक,

राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की त्रैमासिक समाचार पत्रिका का यह नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

इस अंक में छत्तीसगढ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना **" छत्तीसगढ के चार चिन्हारी – नरवा, गरुवा,घुरवा और बाडी : ऐला बचाना है संगवारी "** का विस्तृत वर्णन किया गया है जो कि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा औषधीय पौधों पर आधारित पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणाली को बढावा देने हेतु क्रमशः धमतरी, महासमुंद और बलौदाबजार वन मंडलों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

इस संस्करण में हमनें एक 16 वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता के बारे में भी चर्चा की है जिसे जलवायु परिवर्तन जागरुकता के लिए नोबल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है।

इस अंक में सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन की दिशा में की गई अनेक पहलों संबधी प्रकाशन के बारे में भी बताया गया है तथा हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016 में हुये संशोधन के बारे में भी चर्चा की गयी है।

इस समाचार पत्रिका के अगामी अंकों में सुधार के लिए हम अपने पाठकों की प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत करते हैं।

मुझे उम्मीद है यह नवीन संस्करण आपको पसंद आयेगा।

(मुदित कुमार सिंह)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
निदेशक, राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
तथा राज्य नोडल अधिकारी, जलवायु परिवर्तन
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

विषय-वस्तु

- मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन का संदेश
- "छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी – नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी ऐला बचाना है संगवारी "
- एल.ई.डी स्केल – अप : एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग को तेजी से अपनाने में राज्य स्तरीय समर्थन
- औषधीय पौधों पर आधारित पारंपरिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा चलित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया
- सोलह वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया
- जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की नई राष्ट्रीय वन नीति
- मंत्रिमंडल ने (सीओपी) 24, कातोविसे, पोलैंड के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की
- सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलनता की दिशा में की गई अनेक पहलों के बारे में वृहद प्रकाशन जारी किया
- भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया
- हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016 में संशोधन
- समाचार शीर्षक

मुख्य सचिव महोदय का संदेश

सुनील कुमार कुजूर
मुख्य सचिव
Sunil Kumar Kujur
Chief Secretary

छत्तीसगढ़ शासन
Government of Chhattisgarh

रायपुर, दिनांक 1 FEB 2019

क्षेत्रफल की दृष्टि में छत्तीसगढ़ देश का 10 वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र है साथ ही राज्य की कुल आबादी का 33 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जन जातियों का है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है जिसकी आजीविका का मुख्य आधार कृषि एवं वन है।

जलवायु में होने वाले छोटे–छोटे परिवर्तन ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गंभीर चुनौती के रुप में परिलक्षित होते है। राज्य, देश अपितु संपूर्ण विश्व द्वारा न केवल जलवायु परिवर्तन के हानिकारक परिणामों को कम करने के लिये प्रयास किये जा रहे है बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों से अनुकूलन की दिशा में भी लगातार कार्य किये जा रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन विषयक ज्ञान के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गो के लोग एकजुट होकर इस अभियान में भाग ले सकें।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा राज्य में जलवायु परिवर्तन के हानिकारक परिणामों से निपटनें के लिये लगातार उल्लेखनीय प्रयास किये जा रहे है । त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन जलवायु परिवर्तन विषयक जागरूकता और ज्ञान के प्रसार हेतु केंद्र के महत्वपूर्ण और अभिनव प्रयासों में से एक है।

त्रैमासिक न्यूजलैटर का प्रकाशन अपने लक्ष्यों में सफल हो ऐसी शुभकामना के साथ....

(सुनील कुमार कुजूर)

"छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी – नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी ऐला बचाना है संगवारी "

छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना **"छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी – नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी ऐला बचाना है संगवारी "** को कार्यान्वित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

13 विभागों को इसमें शामिल किया गया है। कृषि विभाग इसकी नोडल एजेंसी होगी। यह समिति योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने के लिए काम करेगी।

नरवा :-

- क्षेत्र के प्राकृतिक जल संसाधन की पहचान और संरक्षण,
- मृदा और जल संरक्षण उपचार,
- सिंचाई की बेहतर सुविधाओं को बढ़ावा देना।

गरुवा :-

- उन्नत मवेशियों की नस्ल को बढ़ावा देना।
- पशुपालन प्रथाओं में सुधार,
- घास की भूमि का विकास,
- स्टाल फीडिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा।

घुरवा :-

- वर्मी–कम्पोस्टिंग, NADEP आदि के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- गैर पारंपरिक ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देना।

बाड़ी :-

- कृषि–बागवानी मॉडल की स्थापना,
- उच्च मूल्य वाली सब्जियों / नकदी फसलों को बढ़ावा देना,
- होम गार्डन को बढ़ावा देना।

एल.ई.डी स्केल – अप : एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग को तेजी से अपनाने में राज्य स्तरीय समर्थन

द क्लाईमेट ग्रुप द्वारा Signify के सहयोग से "LED Scale - Up: State Level Support - Acceleration LED Street Lighting adoption" विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। जिसमें छत्तीसगढ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र भी शामिल हुआ।

द क्लाईमेट ग्रुप, एल.ई.डी के द्वारा उर्जा बचत के लाभों के प्रचार प्रसार करने तथा उसे अपनाने में तेजी लाने के लिए दुनिया भर के शहरों के साथ काम कर रहा है।

वैश्विक जनसंख्या 2050 तक 9.7 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। जिसमें शहर नई तकनीक के माध्यम से उत्सर्जन में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगें।

इस वेबिनार में वक्ताओं ने पारम्परिक प्रकाश व्यवस्था की तुलना में एल.ई.डी. के उपयोग से 50% – 70% उर्जा बचत के बारे में बताया साथ ही एल.ई.डी अपनाने की प्राथमिकता को बढाने के लिए आग्रह किया। साथ ही वेबिनार में वक्ताओं द्वारा विभिन्न देशों तथा राज्यों की ऊर्जा नीतियों की चर्चा करते हुए एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग जैसे प्रयासों को अपनाने पर जोर दिया।

वेबिनार में शामिल मुख्य वक्ताओं के नाम निम्न अनुसार हैं –

- टोनी मार्गन, एलईडी प्रोग्राम मैनेजर– द क्लाईमेट ग्रुप
- सुसैन सीटिंगर, डायरेक्टर, पब्लिक मार्केटींग सेक्टर– सिग्नीफार्ड टायलर मास्टर्स,प्रोग्राम मैनेजर– वेस्टर्न रिवरसाइड कांउसिल ऑफ गवर्नमेंट्स (WRCOG)
- डेविड टेरी, कार्यकारी निदेशक – ऑफ स्टेट एनर्जी ऑफिसियल (NASEO)
- बेन श्वास, वीपी, गर्वनमेंट अफेयर और कम्यूनिकेशन– उर्जा बचत हेतु गठबंधन।

औषधीय पौधों पर आधारित पारंपरिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा चलित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

NAFCC परियोजना अंतर्गत पारंपरिक स्वास्थ्य उपचार पद्धति को बढ़ावा देने के लिए जनवरी से मार्च के बीच तीन वन वनमंडलों (धमतरी, महासमुंद, और बलौदा बाजार) में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा कुल 9 पारंपरिक स्वास्थ्य उपचार शिविर आयोजित किए गए।

धमतरी वन मंडल

धमतरी वन मंडल में मुनईकेरा, दिनकरपुर और भोबलाबहरा गांवों में 20/02/2010 से 21/02/2019 तक कुल 3 मोबाइल स्वास्थ्य उपचार शिविर आयोजित किए गए।

पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सकः— 1. श्री तेजूराम साहू 2. श्री खेमराज सेन 3. श्री यशवंत नेताम 4. श्री रमेश कुमार श्रीमाली 5. श्री जीवराखन मरकाम 6. श्री अजीत कोमरे 7. श्री भानुराम मंडावी

अवलोकनः— धमतरी वन मंडल के स्वास्थ्य शिविरों में कुल 72 लोग लाभान्वित हुए।

महासमुंद वन मंडल

स्वास्थ्य शिविर को जारी रखते हुए के लिए हमारी टीम ने महासमुंद वन मंडल का दौरा किया। महासमुंद वन मंडल के ग्राम पासिद, चुहरी और अमलोर में 22/02/2019 से 23/02/2019 तक कुल 3 मोबाइल स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए।

पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सकः— 1.श्री बैजूराम धीवर 2.श्री सुखचैन हिरवानी 3.श्री दाउराम निषाद 4.श्री राम गोपाल यादव।

अवलोकनः— महासमुंद वन मंडल के स्वास्थ्य शिविरों में कुल 15 लोग लाभान्वित हुए।

बलौदा बाजार वन मंडल

अंत में हमारी टीम ने बलौदा बाजार वन मंडल का दौरा किया। बलौदा बाजार वन मंडल के ग्राम महकोनी, खोसड़ा और दलदली में 25/02/2019 से 26/02/2019 तक कुल ३ मोबाइल स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।

पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सकः— 1.श्री श्याम मैत्री 2. श्री कृपाराम विश्वकर्मा 3. केजुराम पैंकरा 4. रामाधार वेदना

अवलोकनः— बलौदा बाजार वन मंडल के स्वास्थ्य शिविरों में कुल 78 लोग लाभान्वित हुए।

सुबह की हवा लाख रुपये की दवा

द्वाराः—कृपाराम विश्वकर्मा
पारंपरिक स्वास्थ्य चिकित्सक

सोलह वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया

सोलह वर्षीय स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अगस्त 2018 में, थुनबर्ग ने हर दिन स्कूल छोड़ना शुरू कर दिया और इसके बजाय स्वीडिश संसद के बाहर बैठकर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल ध्यान देने की मांग की।

सितंबर 2018 में स्वीडन में आम चुनाव होने के बाद, थुनबर्ग ने हर शुक्रवार को संसद के बाहर बैठना शुरू किया, और तब से दुनिया भर के कई छात्रों को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

एक वर्ष से भी कम समय में, थुनबर्ग ने एक स्वच्छ पृथ्वी के लिए अपने विचारों और मांगों को सामने रखने के लिए विश्व नेताओं की कई सभाओं को संबोधित किया है। जनवरी 2019 में, उसे दावोस में विश्व आर्थिक मंच में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था।

फरवरी 2019 में, थूनबर्ग ने एक यूरोपीय संघ के सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि वह, अन्य बच्चों के साथ, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ रहे हैं, न केवल अपने भविष्य के लिए बल्कि सभी के लिए भी जूझ रहे हैं।

पोलैंड में दिसंबर 2018 में आयोजित कटोविस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस – सीओपी 24 में विश्व नेताओं के सामने अपने संबोधन के बाद थुनबर्ग ने बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की थी। टाइम पत्रिका द्वारा उन्हें 2018 के 25 सबसे प्रभावशाली किशोरों में से एक के रूप में चुना गया था।

Source:- https://scroll.in/video/916709/

जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत की नई राष्ट्रीय वन नीति

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक नई राष्ट्रीय वन नीति 2018 ड्राफ्ट तैयार की है जिसमे सतत वन प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के शमन का प्रस्ताव शामिल है । नई नीति, जिसका उद्देश्य वन आवरण को भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का न्यूनतम एक तिहाई लाना है और घने वन आवरण की रक्षा के लिए सख्त नियम लागू करना है, जो मौजूदा वनों का प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शन करने वाले 1988 के नियमो की जगह लेगा। पिछली नीतियों के विपरीत, जिसने पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव पर जोर दिया, 2018 की नीति जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय चुनौती पर केंद्रित है।

नई नीति में मानव–पशु संघर्ष के मुद्दे को भी शामिल किया गया है तथा इसे कम करने के लिए अल्पावधि और दीर्घकालिक उपायों का प्रस्ताव है। नई नीति में कहा गया है, "त्वरित प्रतिक्रिया, अच्छी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षित कर्मियों की समर्पित टीम, गतिशीलता, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सेवाओं के साथ मजबूत इंटरफ़ेस, बचाव केंद्र, नुकसान के त्वरित मूल्यांकन और उद्देश्य और पीड़ितों को राहत के त्वरित भुगतान अल्पकालिक कार्रवाई का मूल होगा । जंगलों के भीतर और बाहर वन्यजीवों की आबादी की निगरानी और प्रबंधन, संतुलन बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक आधार पर अपनाया जाएगा। "

Source:- https://economictimes.indiatimes.com/

मंत्रिमंडल ने COP-24, कातोविसे, पोलैंड के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2–15 दिसंबर, 2018 तक कातोविसे, पोलैंड में आयोजित यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCC) के बारे में 24वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के दौरान भारत के दृष्टिकोण के बारे में बातचीत करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इस बैठक में पोस्ट– 2020 अवधि के दौरान पेरिस समझौते को लागू करने के लिए दिशा–निर्देशों को अंतिम रूप देने के बारे में ध्यान केन्द्रित किया गया था। भारत का दृष्टिकोण UNFCC के सिद्धांतों और प्रावधानों से निर्देशित था। इसमें इक्विटी और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमता के सिद्धांतों (CBPR–RC) पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया।

भारत ने पेरिस समझौते के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और सामूहिक रूप से पेरिस समझौता लागू करने के लिए अपने वायदों को शामिल करते हुए COP-24 के दौरान अपने नेतृत्व के बारे में प्रकाश डाला। पर्यावरण सुरक्षा के बारे में अपने परम्परागत स्वभाव के अनुरूप भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन की चिंताओं से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये प्रयास जलवायु कार्रवाई की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सौर ऊर्जा से प्राप्त 24 गीगावाट बिजली क्षमता सहित 74 गीगावाट की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को अर्जित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को गति प्रदान की गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौता, ऊर्जा दक्षता प्रयासों जैसे उदाहरणों के माध्यम से इसे सोलर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के अपने उद्देश्य से विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।

Source:- http://pib.nic.in/

COP24·KATOWICE 2018
UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE

सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलनता की दिशा में की गई अनेक पहलों के बारे में वृहद प्रकाशन जारी किया

केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज भारत में जलवायु क्रियाओं के बारे में ''भारत – जलवायु समाधानों का नेतृत्व कर रहा है'' नामक प्रकाशन जारी किया। इस प्रकाशन में जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलनता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के तहत भारत द्वारा की गई प्रमुख कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकाशन को जारी करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दुनिया में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विविध पहलुओं पर कार्य करने वाला दुनिया का एक सक्रिय देश बन गया है।

इस प्रकाशन के जारी किये जाने के बारे में खुशी जाहिर करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि इस प्रकाशन में न केवल जलवायु कार्यवाही के बारे में हमारी उपलब्धियों को उजागर किया गया है बल्कि भविष्य के लिए हमारी तैयारी का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकाशन में जिन पहलों का उल्लेख है वें सतत विकास प्राथमिकताओं के साथ अच्छा संतुलन कायम करते हुए जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का समाधान करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

श्री हर्ष वर्धन ने कहा कि हम सब यह जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक समस्या बन गया है और पूरी दुनिया में लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन ने हमारे पर्यावरण और समाज के सामने गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। आज जलवायु परिवर्तन के बारे में निराश या भयभीत होना तो आसान है लेकिन मेरा हमेशा यह विश्वास रहा है कि हर समस्या का समाधान होता है बस हमें केवल उसे खोजने की जरूरत है। पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की गई अनेक स्वच्छ और हरित विकास पहलों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलनता के बारे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

Source:- http://pib.nic.in/

प्रकाशन में शामिल कुछ प्रमुख पहल :-

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)
- जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (SAPCC)
- FAME योजना - ई-गतिशीलता के लिए
- प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना
- स्वच्छ भारत मिशन

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का उद्घाटन किया गया

वायु प्रदूषण आज की सबसे बड़ी वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। देश भर में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अखिल भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा 10 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में किया गया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, "सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और प्रदूषण के सभी स्रोतों पर ध्यान देने वाले अन्य हितधारकों के साथ सहयोगात्मक और भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण कार्यक्रम को सफल बनता है "। डॉ हर्षवर्धन ने आगे बताया कि उपलब्ध अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और राष्ट्रीय अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए, 2024 तक $PM_{2.5}$ और PM_{10} की 20% सांद्रता में कमी का अस्थायी राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य NCAP के तहत 2017 को आधार वर्ष के रूप में सांद्रता की तुलना हेतु प्रस्तावित किया गया।

"अखिल भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का समग्र उद्देश्य देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाने और जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों को मजबूत करने के अलावा वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए व्यापक शमन क्रियाएं हैं।"

Source:- http://pib.nic.in/

हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016 में संशोधन

देश में हानिकारक कचरे के ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1 मार्च, 2019 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. जी.एस.आर.एक्सएक्स (ई) के माध्यम से हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन) नियम, 2016 में संशोधन किया है।

यह संशोधन व्यावसायिक सुगम्यता तथा मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के साथ–साथ सतत विकास के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करते हुए यह संशोधन किया गया है।

संशोधित हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2019 की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (ईओयू) सहित देश में ठोस प्लास्टिक कचरे के आयात को प्रतिबंधित किया गया है।
- रेशम अपशिष्ट के निर्यातकों को अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति लेने से छूट दी गई है।
- भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान और भारत से इनके निर्यात में खराबी पाए जाने पर निर्यात के एक वर्ष के अंदर सामान का देश में आयात करना होगा। यह पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना होगा।
- जिन उद्योगों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषण) अधिनियम 1974 और वायु (प्रदूषण पर नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत सहमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब हानिकारक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016 के तहत प्राधिकरण की आवश्यकता से भी छूट दी गई है। बशर्ते ऐसे उद्योगों द्वारा उत्पन्न हानिकारक और अन्य अपशिष्ट अधिकृत वास्तविक उपयोगकर्ताओं, अपशिष्ट संग्रहणकर्ताओं या निपटान सुविधाओं को सौंप दिए जाते हैं।

Source:- http://pib.nic.in/

समाचार शीर्षक

If immediate action taken 66% chance of staying below 1.5C

The analysis did not include the possibility of tipping points such as the sudden release of huge volumes of methane from permafrost, which could spark runaway global warming. Other work has shown that keeping within the 1.5C limit is possible if radical action is taken.

The scientists accept their scenario is at the extreme end of ambition, but said it was important to know that meeting the 1.5C target was still physically possible and dependent on the choices made now and in the coming years.

Climate change could be kept in check if a phaseout of all fossil fuel infrastructure were to begin immediately, according to research. It shows that meeting the internationally agreed aspiration of keeping global warming to less than 1.5C above pre-industrial levels is still possible. The scientists say it is therefore the choices being made by global society, which is the obstacle to meeting the goal. The study found that if all fossil fuel infrastructure from now on are replaced by zero-carbon alternatives at the end of their useful lives, there is a 64% chance of staying under 1.5C. In October, the Intergovernmental Panel on Climate Change said the difference between 1.5C of warming and the earlier international target of 2C was a significantly lower risk of drought, floods, heatwaves and poverty for hundreds of millions of people. The study, published in the journal Nature Communications, used computer models to estimate by how much global temperatures would rise if a fossil fuel infrastructure phaseout began immediately. In this scenario, the models suggest carbon emissions would decline to zero over the next four decades.

The climate system is not stopping you [hitting the target], global society is stopping you.

पत्रिका Thu, 17 January 2019
epaper.patrika.com/c/37978173

ग्रीन क्लाइमेट फंड जलवायु परिवर्तन से निपटने में नई शुरुआत

सेकंड आर्टिकल

एन्वायर्नमेंट
डॉ. सीमा जावेद
पर्यावरणविद और संचार रणनीतिकार
Twitter @seemajaved

वर्ष 2019 के आगाज के साथ हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट होकर नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। दुनिया के देश नीतिगत विकल्पों, अभिनव प्रौद्योगिकीय कदमों और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में कमी लाने को तैयार हो गया है। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्थाएं बनाने में मददगार सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों की ओर मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं। इससे पहले दिसम्बर 2018 में पोलैंड के केटोवाइस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने के लिए लगभग 200 देशों के बीच सहमति बनी। इसके अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस के प्री-इंडस्ट्रियल स्तर से नीचे रखा जाना है।

जहां तक भारत का सवाल है 2030 तक उसने 2005 के ग्रीन हाउस गैसों के स्तरों से उत्सर्जन की तीव्रता को 35 फीसदी कम करने और अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने का संकल्प पहले ही व्यक्त किया है। भारत ने अगले दस वर्ष में अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 56.5 फीसदी भाग अक्षय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। लेकिन जब विकासशील देश अपने विकास के शैशव काल में थे तब विकसित देशों ने अत्यधिक उत्सर्जन करके जलवायु परिवर्तन के संकट को दावत दी। इसीलिए अब तक जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत-चीन जैसे विकासशील देश वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए विकसित देशों से ग्रीन क्लाइमेट फंड (जीसीएफ) की मांग करते आ रहे हैं।

इस समझौते के तहत लक्ष्य प्राप्ति के लिए अमीर देशों द्वारा 2020-2025 तक 100 अरब डॉलर की राशि भुगतान करने का प्रावधान है। पहली बार कई विकसित देशों ने विकासशील देशों को वित्तीय सहायता का वचन दिया है। यह ग्रीन क्लाइमेट फंड की पहली औपचारिक पूर्ति की दिशा में महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है, जर्मनी और नार्वे ने घोषणा की है कि वे अपने योगदान को दोगुना कर देंगे। जीसीएफ अनुकूलन कोष में कुल 12.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। इस मौके पर विश्व बैंक ने 2021-2025 की अवधि के लिए 200 अरब डॉलर देने का संकल्प किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का लक्ष्य हासिल होने से सिर्फ वायु प्रदूषण में कमी आने से दुनिया भर में 2050 तक 10 लाख लोगों की जान बच सकती है। अल्प कार्बन ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से न सिर्फ वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि स्वास्थ्य संबंधी त्वरित फायदे के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। विशेषज्ञों के अनुमान से जो संकेत मिल रहे हैं, उससे जलवायु संबंधी कार्यों से जो स्वास्थ्य संबंधी लाभ होगा उसका मूल्य वैश्विक स्तर पर राहत संबंधी नीतियों की लागत का दोगुना होगा। ऐसे में विकसित देशों द्वारा जिम्मेदारी निभाने के लिए उठाए गए इस कदम से नए साल में जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने की राह खुली है और एक नए युग का आगाज हुआ है।

Editorial Team

- श्री मुदित कुमार सिंह (मुख्य संपादक)
- डॉ राजेश गुप्ता
- डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव
- श्री एस. एस बजाज
- श्री मानस उज्जैनी
- श्री अभिनव अग्रहरि

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर
विधानसभा के पास, बलौदा बाजार रोड, जीरो प्वाइंट
रायपुर – 493111, छत्तीसगढ़
फोन : 0771 – 2285120
ईमेलः chhattisgarh.sccc@gmail.com
वेबसाइट : www.cgclimatechange.com